काष्ठ उद्योग के लिए लाइसेंस का विकल्प तलाशेगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार अकृष्ट काष्ठ व कृषि वानिकी काष्ठ का उपयोग करने वाले उद्योगों की अनुमति के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कराएगी। इससे इन सेक्टर के उद्योगों से जुड़े प्रस्ताव पर कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।

सरकार के समक्ष सेंचुरी प्लाई, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज व सत्यम डेकोर आदि की ओर से निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। पर, वन लाइसेंस पर एनजीटी के स्थगनादेश के कारण निवेश से जुड़ी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें निवेशकों ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुसार एमडीएफ संयंत्रों को अकृष्ट काष्ठ (गोल ब्लाकों का उपयोग न करके) के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। एक निवेशक ने प्रत्यावेदन के जरिए बताया कि अकृष्ट काष्ठ का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सरकार केवल पंजीकरण के जरिए इस तरह के उद्योगों को अनुमति दे सकती है। इस तरह की पंजीकरण प्रक्रिया पहले से ही आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में है।

वन विभाग को अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश

निवेशक का दावा- आंध्र प्रदेश में पंजीकरण से ही मिल जाती है अनुमति

इमारती काष्ठ उद्योग का होगा सर्वेक्षण

शासन ने एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक वन विभाग को इमारती काष्ठ उद्योग के उत्पाद और खपत की सर्वे कार्यवाही पूरा करने का निर्देश दिया है।

निवेशकों की बात सुनने के बाद वन विभाग को अकृष्ट काष्ठ और कृषि वानिकी काष्ठ का उपयोग करने वाले उद्योगों की अनुमति के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर विश्लेषण रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। विभाग की रिपोर्ट आने के बाद इस समस्या के समाधान के फार्मूले पर फैसला होगा।

शामली में रूस लगाएगा वुड फैक्टरी, पापुलर वुड का करेगा आयात

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि फि क्की और ब्रिटिश चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ होने वाले एमओयू की अड़चनों को जल्द दूर करें। उन्होंने बताया कि रूस, शामली में वुड फैक्टरी स्थापित कर पॉपुलर वुड का आयात करेगा। इससे यूपी व रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दी जानकारी

कहा- फिक्की व ब्रिटिश चैंबर ऑफ कॉमर्स से एमओयू की अड़चन दूर करें

सिद्धार्थनाथ बोले- भाषा दक्षता विकास केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार करें

महाना शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ विधानभवन में इन्वेस्ट यूपी की बैठक में बोल रहे थे।

बैठक में सिद्धार्थनाथ ने निर्देश दिए कि औद्योगिक समूहों से एमओयू के लिए इन्वेस्ट यूपी एमओयू ड्राफ्ट बनाए तथा प्रदेश में स्थापित होने वाले डाटा सेंटर पार्क की स्थापना में तेजी लाएं। उन्होंने इसके लिए अमेजन व फि ल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भाषा दक्षता विकास का केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। मुख्य सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि निवेश प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान करें, जिससे निवेशकों को कोई परेशानी न हो।

माइक्रोसॉफ्ट से लखनऊ में होगा एमओयू : सिद्धार्थनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एमओयू साइन करने से जुड़े कामों में तेजी लाने और लखनऊ में एमओयू साइन कराने के निर्देश दिए। कहा, कनाडा और जापान की कंपनियों ने कृषि क्षेत्र में निवेश की रुचि दिखाई है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों से समन्वय कराया जाए। ब्यूरो